



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 29 अक्टूबर, 2003/7 कार्तिक, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त विभाग  
(वेतन परिशोधन अनुभाग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 22 मिनम्बर, 2003

संख्या-फिन-(पी0 आर0) बी0 (7)-3/98-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का 10) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायिक अधिकारियों के वेतन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन नियतन) नियम, 2003 है।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,—

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है ;

(ख) “मूल वेतन” से न्यायिक अधिकारी द्वारा धारित पद के विद्यमान वेतनमान में उसके द्वारा आहरित मासिक रकम या जिसके लिए वह संवर्ग में अपने पद के कारण हकदार है, अभिप्रेत है, अनुग्रह पूर्वक वार्षिक वेतन वृद्धि और अतिरिक्त वेतन, यदि कोई हो, इसके अन्तर्गत है परन्तु विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन इसमें सम्मिलित नहीं होगा ;

- (ग) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;
- (घ) "विद्यमान वेतनमान" से धारित पद की बाबत पूर्व संशोधित वेतनमान या न्यायिक अधिकारी को प्रथम जनवरी, 1996 से अनुदत्त वैयक्तिक वेतन, चाहे अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में हो, अभिप्रेत है ;
- (ङ) "संशोधित वेतन" से इन नियमों के नियम 5 के अश्वीन संशोधित वेतनमान में नियत किया जाने वाला न्यायिक अधिकारी का मूल वेतन अभिप्रेत है ;
- (च) "संशोधित वेतनमान" से अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतनमानों के सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट वेतनमान अभिप्रेत है ; और
- (छ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. मास्टर वेतनमान.—न्यायिक अधिकारियों का वेतन 9000-250-10750-300-13150-350-15950-400-19150-450-21850-500-24850 रुपए के मास्टर वेतनमान के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

4. वेतनमानों का संशोधन.—इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से, अनुसूची के स्तम्भ 3, में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतनमानों के सामने उसके स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट वेतनमानों को 1-1-1996 से संशोधित किया गया समाप्त जाएगा :

परन्तु संशोधित वेतनमानों में वेतन नियन्त्रण के प्रयोजन के लिए, विद्यमान वेतनमान में प्रथम जनवरी, 1996 को यथा विद्यमान, मूल वेतन और मंहगाई भत्ता हिस्सा में लिया जाएगा और अन्तरिम राहत जिसे यद्यपि प्रथम जुलाई, 1996 से मंजूर किया गया है, परन्तु परिलब्धियों की संगणना के प्रयोजन के लिए इसे प्रथम जनवरी, 1996 से नोशनल आधार पर हिस्सा में लिया जाएगा :

परन्तु यह और कि न्यायिक अधिकारी का वेतन प्रथम जनवरी, 1996 से नोशनल आधार पर नियत किया जाएगा परन्तु वास्तविक आर्थिक लाभ प्रथम जुलाई, 1996 से ही दिए जाएंगे ।

5. संशोधित वेतनमान में वेतन का नियन्त्रण.—(1) न्यायिक अधिकारियों का वेतन प्रथम जनवरी, 1996 को संशोधित वेतनमान में निम्नलिखित रीति में नियत किया जाएगा, अर्थात् :—

- (i) विद्यमान वेतनमान में 1-1-1996 को मूल वेतन जमा उस पर दस प्रतिशत की वृद्धि ;
- (ii) प्रथम जनवरी, 1996 को यथा विद्यमान मूल वेतन पर 1510 (1960-100) के ए0 आई0 सी0 पी0 आई0 स्तर पर अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता ;
- (iii) घित्त विभाग के पत्र संख्या फिन (पी0आर0) बी0 (7)-3/98, तारीख 6 जून, 1998 द्वारा मंजूर, प्रथम जनवरी, 1996 को यथा विद्यमान मूल वेतन और मंहगाई भत्ते पर, चालीस प्रतिशत अन्तरिम राहत ; और
- (iv) उन्मुक्त संगणना के पश्चात्, 1-1-1996 को यथा विद्यमान, वेतनमान में, मूल वेतन पर दस प्रतिशत फिटमेट अतिरिक्त प्रमुविधा अनुज्ञात की जाएगी और तत्पश्चात् न्यायिक अधिकारी का वेतन संशोधित वेतनमान में निम्नलिखित रीति में नियत किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि यथा पूर्वोक्त संगणित वर्तमान परिलब्धियों का योग संशोधित वेतनमान के न्यूनतम से कम है तो वेतन संशोधित वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा ;

- (ख) यदि इस प्रकार संगणित वर्तमान परिलब्धियों का योग संशोधित वेतनमान में किसी प्रक्रम (स्टेज) के अनुरूप होता है तो संशोधित वेतनमान के उसी प्रक्रम (स्टेज) पर ;
- (ग) यदि इस प्रकार संगणित वर्तमान परिलब्धियों का योग संशोधित वेतनमान में दो प्रक्रमों के मध्यवर्ती है तो उच्चतर प्रक्रम (स्टेज) पर ; और
- (घ) यदि इस प्रकार संशोधित वर्तमान परिलब्धियों का योग संशोधित वेतनमान के अधिकतम से अधिक है तो संशोधित वेतनमान और अन्तर यदि कोई हो, का अधिकतम वैयक्तिक वेतन माना जाएगा ।

(2) संशोधित वेतनमानों में वेतन नियत करने समय निम्नलिखित कारकों पर भी विचार किया जाएगा ;  
अर्थात् :—

- (क) यदि कोई न्यायिक अधिकारी जो, विद्यमान वेतनमान में, संसर्ग संवर्ग के और तदनु न्युक्त अपने से वरिष्ठ के बराबर या कम वेतन ले रहा है, संशोधित वेतनमान में अपनी आगामी वेतन वृद्धि, ऐसे वरिष्ठ से पूर्वतम तारीख को लेता है जिससे कि उसका वेतन ऐसे वरिष्ठ से एक प्रक्रम (स्टेज) उच्चतर हो जाता है तो वरिष्ठ को आगामी वेतन वृद्धि उसी तारीख से प्रदान की जाएगी जिसको कि कनिष्ठ अधिकारी संशोधित वेतनमान में अपनी आगामी वेतनवृद्धि लेता है ;
- (ख) यदि 1-1-1996 से पूर्व उच्चतर पद पर प्रोन्नत कोई न्यायिक अधिकारी संशोधित वेतनमान में अपने से कनिष्ठ से कम वेतन लेता है तो उसका वेतन, उच्चतर पद पर उसके कनिष्ठ के वेतन के बराबर, कनिष्ठ की प्रोन्नति की तारीख से, बढ़ा दिया (स्टेपड अप) जाएगा ;
- (ग) खण्ड (क) और (ख) के अधीन प्रयुक्त हुए केवल उपी दशा में अनुज्ञेय होंगी जब संशोधित वेतनमान में वेतन नियतन उपयोजन के परिणामस्वरूप विषमता उद्भूत होती है ।

6. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख.—(1) संशोधित वेतनमान में न्यायिक अधिकारी की वेतनवृद्धि की आगामी तारीख वह तारीख होगी जिसको कि उसने वेतनवृद्धि ली होती यदि वह विद्यमान वेतनमान में निरन्तर रहता ।

(2) यदि कोई न्यायिक अधिकारी इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन संशोधित वेतनमान में अपनी आगामी वेतनवृद्धि लेता है और इसके परिणामस्वरूप अपने से वरिष्ठ, जिसकी आगामी वेतनवृद्धि पश्चात्पूर्व तारीख को देय होती हो, से उच्चतर वेतन के लिए पात्र हो जाता है, तो ऐसे वरिष्ठ का वेतन उस तारीख से जिसको कि कनिष्ठ उच्चतर वेतन का हकदार हो जाता है, कनिष्ठ के वेतन के बराबर पुनः नियत किया जाएगा और यदि जहां न्यायिक अधिकारी का वेतन इन नियमों के नियम 5 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के निबन्धनों के अनुसार बढ़ा दिया (स्टेपड अप) जाता है तो आगामी वेतनवृद्धि बारह मास की अपेक्षित अर्हत-सेवा पूर्ण करने के पश्चात् प्रदान की जाएगी ।

(3) जहां कोई न्यायिक अधिकारी 1-1-1996 को या उसके पश्चात्, अथास्थिति, प्रारम्भिक वेतनमान या चयन ग्रेड या सुपर टाईम वेतनमान के अधिकतम पर रुक (हैल्ड अप) जाता है तो उसे अनुग्रहपूर्वक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी, जब तक उसे उसी दर पर विधरित नहीं किया गया है जो कि मास्टर वेतनमान में, उस प्रक्रम (स्टेज) के पश्चात्, जिस पर कि वह रुक (हैल्ड अप) गया था, दी गई है, परन्तु किसी भी दशा में न्यायिक अधिकारी का मूल वेतन चौबीस हजार आठ सौ पचास रुपए से अधिक नहीं होगा ।

7. एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम.—न्यायिक अधिकारी, हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए पात्र होंगे ; अर्थात् :—

- (क) यह कि पदधारी आगामी उच्चतर पद पर प्रोन्नत नहीं हुआ है ;

- (ख) यह कि इस प्रसुविधा का प्रदत्त किया जाना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गठित इसके वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति द्वारा पात्र पदधारी के कार्य और निष्पादन के मूल्यांकन के अध्वधीन होगा ;
- (ग) यह लाभ उस पदधारी को अनुज्ञेय नहीं होगा जिसने किसी भी आधार पर नियमित प्रोन्नति अस्वीकार की है ;
- (घ) जहां सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) या सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के संवर्ग का अधिकारी, जिसे एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का लाभ दिया गया है, गुणागुण और बरीयता के आधार पर अपनी बारी पर उच्चतर संवर्ग में कृत्यकारी प्रोन्नति से इन्कार करता है तो उसे मूल वेतनमान पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा ।

8. जिला न्यायाधीशों को चयन ग्रेड और सुपर टाईम वेतनमान की प्रसुविधा.--(1) चयन ग्रेड का लाभ उन न्यायाधीशों को दिया जाएगा जिनका, गुणागुण एवं बरीयता पर निर्धारण के आधार पर, संवर्ग में निरन्तर सेवाकाल पांच वर्ष से कम न हो ; और

(2) सुपर टाईम वेतनमान की प्रसुविधा उन जिला न्यायाधीशों को दी जाएगी, जिनका, चयन ग्रेड जिला न्यायाधीशों के रूप में , निरन्तर सेवाकाल तीन वर्ष से कम न हो ।

9. बकाया का संदाय :—न्यायिक अधिकारियों के वेतनमानों में संशोधन के कारण प्रथम जुलाई, 1996 से 31 मार्च, 2003 तक के बकाया का संदाय सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाएगा और उन न्यायिक अधिकारियों के मामले में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिन्हें 31 दिसम्बर, 2003 तक सेवानिवृत्त होना है तथा अपना सामान्य भविष्य निधि खाता बन्द कर चुके हैं, को बकाया का संदाय नकद किया जाएगा ।

10. निर्वचन.—यदि इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उपगत होता है तो सरकार उसे निश्चित करेगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

11. निरसन.—सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ0 आई0 एन0 (पी0 आर0) बी (7)-1/98, तारीख 18 सितम्बर, 2001 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

अनुसूची  
(नियम 4 देखें)

क्रम संख्या	सेवा का नाम	विद्यमान वेतनमान (रुपयों में)	संशोधित वेतनमान रुपए	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
(i)	उप-न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट	(i) 2200—4000 (ii) 3000—4500 (8 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात् वरिष्ठ वेतनमान) । (iii) 4125—5600 (18 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात् चयन ग्रेड) ।	9000—14550	सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के रूप में पुनः पदाभिहित ।

1	2	3	4	5
(ii)	वरिष्ठ उप-न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ।	यथोपरि	12850—17550	सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के रूप में पुनः पदाभिहित ।
(iii)	जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ।	3000—5600 5000—6700 (8 वर्ष के सेवाकाल के पश्चात् चयन ग्रेड) ।	16750—20500	जिला न्यायाधीश के रूप में पुनः पदाभिहित ।

आदेश द्वारा,

एस० एस० परमार,  
प्रधान सचिव (वित्त)।

[Authoritative English text of this Government Notification No: FIN-(PR)B(7)-3/98-III, dated 22nd September, 2003 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution].

### FINANCE DEPARTMENT (Pay revision section)

### NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd September, 2003

**No. FIN-(PR)B(7)-3/98-III.**—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 10 of 2003), is pleased to make the following rules to regulate the pay of the Judicial Officers, namely:—

1. *Short title.*—These rules may be called the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay Fixation) Rules, 2003.

2. *Definitions.*—(1) In these rules, unless there is anything repugnant to the subject or context,—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 ;

(b) “basic pay” means the amount drawn monthly by a Judicial Officer in the existing scale of the post held by him or to which he is entitled by the reasons of his position in a cadre including ex-gratia annual increment(s) and additional pay, if any, but shall not include Special Pay and Personal Pay ;

(c) “Government” means the Government of Himachal Pradesh ;

(d) “existing pay scale” means the pre revised pay scale in respect of a post held or a personal scale allowed to a Judicial Officer as on 1st day of January, 1996, whether in a substantive or officiating capacity ;

(e) "revised pay" means basic pay of a Judicial Officer to be fixed in the revised scale under rule 5 of these rules ;

(f) "revised pay scale" means the pay scales specified in column 4 of the Schedule, as against the existing pay scales specified in column 3 thereof; and

(g) "Schedule" means the Schedule appended to these rules.

(2) The words and expressions used, but not defined in these rules shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. *Master pay scale.*—The pay of Judicial Officers shall be regulated in accordance with the Master pay scale of Rs. 9000-250-10750-300-13150-350-15950-400-19150-450-21850-500-24850.

4. *Revision of pay scales.*—From the date of commencement of these rules the pay scales specified in column No. 4 of the Schedule as against the existing pay scales specified in column No. 3 thereof shall be deemed to have been revised with effect from 1-1-1996 :

Provided that for the purpose of fixation of pay in the revised pay scales the basic pay and dearness allowance as on 1st day of January, 1996, in the existing pay scales shall be taken into account and the Interim Relief, though sanctioned with effect from 1st July, 1996, but for the purpose of computation of emoluments it shall be taken into account with effect from 1-1-1996 on notional basis :

Provided further that the pay of a Judicial Officer shall be fixed on notional basis with effect from the 1st day of January, 1996 but the actual monetary benefit shall be given only with effect from the 1st day of July, 1996.

5. *Fixation of pay in the revised pay scale.*—(1) The pay of a Judicial Officer in the revised pay scale shall be fixed on 1-1-1996 in the following manner, namely :—

- (i) basic pay in the existing scale as on 1-1-1996 plus 10% enhancement thereon ;
- (ii) dearness allowance admissible on the original basic pay as on 1st January, 1996 at AICPI level of 1510 (1960=100) ;
- (iii) 40% interim relief on the original basic pay and dearness allowance as on 1-1-1996 sanctioned *vide* Finance Department letter No. Fin-(PR)B(7)-3/98, dated 6th June, 1998 ; and
- (iv) after the aforesaid calculation, 10% fitment additional benefit on the basic pay in the existing pay scale as on 1-1-1996, shall be allowed and thereafter, the pay of a Judicial Officer in the revised pay scale shall be fixed in the following manner, namely:—
  - (a) in case the aggregate of the present emoluments as aforesaid computed is less than the minimum of the revised pay scale, then the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay scale ;
  - (b) in case the aggregate of the present emoluments so computed corresponds to a stage in the revised pay scale, at that stage of the revised scale ;
  - (c) in case the aggregate of the present emoluments so computed is intermediate between two stages in the revised pay scale, then at the higher stage ; and

(d) in case the aggregate of the present emoluments so computed is more than the maximum of the revised pay scale, then at the maximum of the revised pay scale and the difference, if any, be treated as personal pay.

(2) While fixing the pay in the revised pay scales, the following factors shall also be taken into account, namely:—

(a) in case, a Judicial Officer drawing pay in the existing pay scale, equal to or less than that of his senior in the same cadre and similarly appointed, draws his next increment in the revised pay scale on the date earlier than such senior whereby his pay is raised to a stage higher than that of such senior, the next increment of the senior shall be granted on the same date on which the junior officer draws his next increment in the revised pay scale ;

(b) in case, a Judicial Officer promoted to a higher post before 1-1-1996 draws less pay in the revised pay scale than his junior, his pay shall be stepped up equal to the pay of his junior in the higher post from the date of promotion of the junior ; and

(c) the benefits under clauses (a) and (b), shall be admissible only in case the anomaly has arisen due to the consequence of the application of the fixation of pay in the revised pay scales.

6. *Date of next increment.*—(1) The next date of increment of a Judicial Officer in the revised pay scale shall be the date on which he would have drawn the increment had he continued in the existing pay scale.

(2) In case a Judicial Officer draws his next increment in the revised pay scale under sub-rule (1) of this rule and thereby becomes eligible for higher pay than his senior whose next increment falls due at a later date, the pay of such senior shall be refixed equal to the pay of the junior from the date on which the Junior becomes entitled to higher pay and in case where the pay of a Judicial Officer is stepped up in terms of clause (b) of sub-rule (2) of these rules, the next increment shall be granted after completing requisite qualifying service of 12 months.

(3) Where a Judicial Officer is held up at the maximum of the initial scale or selection grade or super time scale, as the case may be, on or after the 1st day of January, 1996, he shall be allowed ex-gratia annual increment, unless it is withheld at the same rate, as is given in the Master Scale after the stage at which he was held up, but in no case the basic pay of a Judicial Officer shall exceed twenty four thousand eight hundred fifty rupees.

7. *Assured Career Progression Scheme.*—The Judicial Officers shall be eligible for Assured Career Progression Scheme as specified in the Schedule appended to the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 subject to the following conditions, namely:—

(a) that the incumbent is not promoted to the next higher post ;

(b) that the conferment of this benefit shall be subject to appraisal of the work and performance of the eligible incumbent by a Committee of Senior Judges of the Himachal Pradesh High Court constituted by it ;

(c) that this benefit shall not be admissible to an incumbent who has declined regular promotion on any grounds ;

(d) in case where an officer in the cadre of Civil Judge (Junior Division) or Civil Judge (Senior Division), who has been provided the benefit of Assured Career Progression

Scheme, refuses functional promotion to higher cadre on his turn on merit and seniority, he shall be reverted to the original pay scale.

8. *Benefit of Selection Grade and Super Time Scale to District Judges.*—(1) The benefit of Selection Grade shall be given to those District Judges, who have not less than five years continuous service in the cadre on the basis of assessment on merit-cum-seniority ; and

(2) The benefit of Super Time Scale shall be given to those District Judges, who have not less than three years continuous service as Selection Grade District Judges.

9. *Payment of arrears.*—The payment of arrears from 1st July, 1996 to 31st March, 2003 on account of revision of pay scales to the Judicial Officers shall be credited to the General Provident Fund Account of the concerned Judicial Officer and in case of those Judicial Officers who have retired or who are to retire from the service by the 31st December, 2003 and have closed their General Provident Fund Accounts, the arrears shall be paid in cash.

10. *Interpretation.*—If any question arises in relation to interpretation of any of the provisions of these rules, the Government shall decide the same and its decision shall be final.

11. *Repeal.*—The Notification No. FIN-(PR)B(7)-1/98, dated 18th September, 2001 issued by the Government is hereby repealed.

### SCHEDULE

(See rule 4)

Sl. No.	Name of Service	Existing Pay Scale in rupees	Revised Pay Scale in rupees	Remarks
1	2	3	4	5
(i)	Sub Judge-cum-Judicial Magistrate.	(i) 2200—4000 (ii) 3000—4500 (Senior Scale after 8 years of service). (iii) 4125-5600 (Selection grade after 18 years of service).	9000-14550	Redesignated as Civil Judge (Junior Division.).
(ii)	Senior Sub-Judge-cum--Chief Judicial Magistrate.	-do-	12850—17550	Re-designated as Civil Judge (Senior Division.).
(iii)	District and Sessions Judges/Additional District and Sessions Judges.	3000—5600 5000—6700 (Selection grade after 8 years of service).	16750—20500	Re-designated as District Judge.

By order,

S. S. PARMAR,  
Principal Secretary (Finance).